

April, 1975, adopted the following motion in regard to the presentation of the Report of the Joint Committee of the Houses on the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Bill, 1974:—

"That the time appointed for the presentation of the Report of the Joint Committee of the Houses on the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Bill, 1974 be further extended up to the first day of the Ninety-third Session of the Rajya Sabha."

- (ii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 26th April, 1975, passed, in accordance with the provisions of article 368 of the Constitution of India, without any amendment, the Constitution (Thirty-eighth Amendment) Bill, 1975, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 23rd April, 1975."
- (iii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 26th April, 1975 passed, in accordance with the provisions of article 368 of the Constitution of India, without any amendment, the Constitution (Thirty-seventh Amendment) Bill, 1975 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 23rd April, 1975."

12.04 Hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

PUNJAB GOVERNMENT'S REPORTED REFUSAL OF PERMISSION TO FOOD CORPORATION OF INDIA FOR WHEAT PROCUREMENT IN THE STATE.

SHRI HARI SINGH (Khurja): I call the attention of the Minister of Agriculture and Irrigation to the following

13—2 LSS/ND/75

matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

"The reported refusal of permission to the Food Corporation of India by the Punjab Government to enter the State grain market for wheat procurement due to non-payment of sales tax amounting to Rupees nine crores."

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): Sir There have been some reports in the Press to the effect that unless the Food Corporation of India settles the sales tax arrears which the State Government of Punjab claims, are due to them from the Food Corporation of India, the Corporation will not be allowed any share in procurement of wheat in Punjab during the current marketing season. There is, however, no official communication to this effect from the Punjab Government. The work to be assigned to the Food Corporation of India in the procurement of wheat in Punjab during the current season (1975-76) is still to be decided by that Government. The question whether the sales tax referred to is payable or not is pending in a writ in the Punjab and Haryana High Court and is sub-judice.

श्री हरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, एफ सी आई हिन्दुस्तान में बहुत ही डीलाटाला, लापरवाह और अष्टाचार का एक फेडरेशन आफ करप्शन आफ इंडिया है। एक नहीं, सैकड़ों तरह की इस विभाग की बर्गलिंग की शिकायतें होती रही हैं। अखबारों की कटिंग्स से मालूम पड़ता है कि 1973-74 में 22 करोड़ रुपये का ट्रांजिट में लॉस हो गया। यह महकमा बड़ा ही गोलमाल का महकमा है और इसमें कोई काम चुस्ती के साथ, इमानदारी के साथ नहीं हो पाता है। इस महकमे पर माननीय मंत्रीजी का भी कोई ग्रिप नहीं मसूम पड़ता है, क्योंकि मैं कई बससे इनकी जानकारी में लाया लेकिन मंत्री महोदय

[श्री हरी सिंह]

कहते थे कि यह आटोमोमस बाडी है, मैं इसको छू नहीं सकता। मैं आपकी जानकारी में यह बात लाना चाहता हूँ।

हमारे जिले में एफ० सी० आई० के गोदाम बन रहे थे। जिस जमीन पर वह बन रहे थे वह जमीन ठीक नहीं थी और ऊँचे दामों पर इनको मिल रही थी। हम चपरामी की तरह दौड़-दौड़कर इनके पास गये, जिन्हे साहब के पास गये लेकिन हमारी बात इनके गले नहीं उतरी। आखिर लड-झगड़कर हमने इनको ठीक जगह दिलाई जिसमें 8 लाख रुपये का मुनाफा हुआ। एफ० सी० आई० के भ्रष्टाचार की इतने बड़ी क्या एग्जाम्पल हो सकती है। जिला बुलन्दशहर यहां से 40 मील की दूरी पर है, सब लोग देख सकते हैं।

यह महकमा सुनने वाला नहीं है, यह भ्रष्टाचार का अड्डा है। इसमें जितने कर्मचारी हैं, इन्स्पेक्टर से लेकर ऊपर तक, न मालूम कितना रूपया इन्होंने कमा लिया है। 9 करोड़ रुपये का मसला पंजाब सरकार का है। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि श्री गणेश जैसे मंत्री को इस काम में लगा दें और एफ० सी० आई० के बड़े अफसरों के घरों पर छापे मारे जायें तो 9 करोड़ रूपया इनके घरों से निकल आयेगा जो कि बेईमानी, गोलमाल, रिश्वत और भ्रष्टाचार के द्वारा इन लोगों ने हासिल किया है।

अखबारों के जरिये मालूम पड़ता है कि पंजाब सरकार के फूड मंत्री ने सैकड़ों बार एफ० सी० आई० की शिकायत की है। उन्होंने गेहूं खरीदने के मोक्रे के पहले ही कहा था कि हम गेहूं की खरीददारी नहीं होने देंगे।

मैं जानना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार इस पर भी अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांधे बैठी रही? जब देश को प्रोक्योरमेंट की आवश्यकता है तो केन्द्रीय सरकार ने इस और ध्यान क्यों नहीं दिया?

पंजाब की सरकार क्यों खरीदने दे, जब कि 9 करोड़ रुपये उसके बाकी है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या केवल मेल्सटैकम की वजह से ही वह गेहूं नहीं खरीदने दे रहे हैं, या और भी कोई कारण है? वहां के मंत्री वक्तन-फ-वक्तन कहते रहे हैं कि अनाज के दाम सही नहीं मिल रहे हैं, कभी चावल के सिलमिले को लेकर ऐसा कहते रहे हैं। वह कई बार केन्द्रीय सरकार के बारे में स्टेटमेंट बाजी करते रहे हैं। इन मारी बातों की तरफ केन्द्रीय सरकार का ध्यान क्यों नहीं गया? क्यों नहीं केन्द्रीय सरकार ने पूछा कि पंजाब की सरकार प्रोक्योरमेंट के मामले में क्यों अड़गा लगा रही है? यही नहीं, स्टेटमेंट में कहा गया है कि धनराशी का मसला तय नहीं हुआ है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में रिट दायर हो गये हैं। आखिर यह नौबत क्यों आ गई? दो सरकारों में मुकद्दमे चल रहे हैं जब कि वहां भी कांग्रेस की सरकार है और केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार है। आखिर यह मुकद्दमेबाजी की नौबत क्यों आई? मालूम पड़ता है कि एफ० सी० आई० अपने काम में दिलचस्पी नहीं ले रहा था, इसीलिये यह झगड़े बढ़ें। इन छोटे-छोटे झगड़ों से तो देश में बंटवारे की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। आज इस छोटे से मुद्दे को लेकर पंजाब ने झगड़ा खड़ा किया है, कल तमिलनाडु, बंगाल और आसाम झगड़े

खड़े करेंगे। तो यह देश के लिये बड़ा घातक इश्यू बन जाता है।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि एफ० सी० आई० ने पहले ही पंजाब सरकार से इस मामले को क्यों नहीं सुलझाया? यह सेल्स टैक्स कितने समय का बाकी है? जो रिट दायर हुआ है, उसके क्या मुद्दे हैं? अभी तक यह क्यों नहीं तय हो पाये हैं। केन्द्रीय सरकार को यह सेल्स टैक्स का रुपया पंजाब सरकार को देना चाहिये।

यह महकमा इस कदर लापरवाह है कि इसकी दिलचस्पी देश के अनाज के सम्बन्ध में नहीं है। यह सुस्ती और लापरवाही की जड़ है। मेरी सरकार में मांग है कि इस महकमे को खत्म करना चाहिये, वाइंड-अप करना चाहिये, वरना यह फूड समस्या को सुलझाने के बजाये और बिगाड़ने पर उतारू है। मंत्री महोदय का इस महकमे पर कोई अधिकार मालूम नहीं होता है।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इसमें चुस्ती लाने के लिये कौन से नये कदम उठाने जा रहे हैं जिससे यह महकमा एफीशियेन्ट हो सके और फूड प्रोक्योरमेंट में जो दिक्कतें आती हैं वह न आ पाये।

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: May I submit that procurement of wheat would not be affected in any way, whether a particular agency is in the procurement operation or not, because the State Government has its own procurement agency and they have been procuring sizeable quantities in the past also. In addition to that, the Punjab Government has set up its own Civil Supplies Corporation. Naturally they are interested in entrusting something to the Corporation also. The Food Corporation of India, being an all India public sector undertaking, have been interested that they should also get an

appropriate share in procurement. This is a matter which we are discussing with the Punjab and the Haryana Government, and I think that an amicable settlement will come about, though at the moment there is some misunderstanding about the sales-tax matter pending in the High Court. But, as far as procurement is concerned, neither the farmers will be affected nor the procurement operation will be affected, even if there is some delay in settling or sorting out the matter though we would like to sort out this matter as early as possible.

The hon. Member has asked the factual position as to what are the arrears and since when they are pending. This is a case of arrears of sales-tax generally on rice purchased; from 1972 onwards the arrears have been pending because the matter is *sub judice*, it became a matter of dispute. After all, the hon. members, before making any remarks, should also appreciate that the Food Corporation of India is also legal entity and if, suppose, a legal point is raised, whether tax is payable or not, naturally the Food Corporation has to abide by the legal advice. Whether a particular transaction, levy collection from farmer, amounts to sale or not, that was a technical point. Because it is compulsory acquisition, sales-tax may not be leviable. That was how the original dispute started. Since the matter, is *sub judice*, I would not like to express any opinion. As far as we are concerned, even if something happens in the court, whether it goes in favour of Punjab or Haryana or against them, we are very much interested in settling the matter with Punjab and Haryana Government. At the moment the High Court has completed the hearing; the judgment is about to be delivered. At this moment, the hon. members will appreciate, it is very difficult for the Government of India to come to any conclusion immediately. Perhaps the judgment may be out in a week's time or so. Then, whatever may be the judgment, the Government of India would like to settle the matter with the Governments of Punjab and Haryana and would not like to stand on technicalities with regard to these matters.

The other complaints of the hon. Member, I think, are not justified and I hope he will forgive me if I do not refer to

[Shri Annasaheb P. Shinde] them. He referred to the general operations of the Food Corporation of India. He also referred to the strike period and other things and that particularly in Bihar the godowns are not operating well. We are aware of that. I do not think that the Food Corporation's management has much to do. That matter can be discussed separately.

SHRI PRABODH CHANDRA (Gurdaspur): The hon. Minister tried to side-track the issue by saying that it is *sub judice*. May I know from the Minister, for how long has the Government of Punjab been pressing them to avoid going to the court and that the Government of India should come to some sort of an agreement?

Secondly, he has said that there is some dispute. May I know what is the position? Is the FCI allowed to make purchases of wheat in Punjab or not?

Why has no action has been taken? At least a dozen times the Minister of Punjab came here and asked the Food Corporation people as well as the Minister concerned that it does not look nice that the Governments of Punjab and Haryana should go to the court against a sister government and that some settlement should be made. But the Government of India did not pay any attention all these three years.

It is a fact that the FCI is not allowed to make purchases in the Punjab. It is only a newspaper report. They have been intimated that the FCI will not be allowed to make purchases. I want to know the actual position about it.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: I do not think I did try to side-track the issue. In fact, as I submitted, this is a legal dispute which relates to a High Court case and when the case is pending before the High Court, naturally, it was very difficult for the Government of India to come to any conclusion about the matter.

Then, Sir, it is not that out of court efforts were not made. In fact, recently my senior colleague, Shri Jagjivan Ram, discussed this matter with the Food Minister of Punjab. I myself had an occasion

to discuss this matter with him and also the Chief Minister of Haryana. Yesterday also and also to-day morning I tried to contact the Chief Ministers of Punjab and Haryana. There is an anxiety on both sides that this matter should be settled. I think as soon as the judgment is out, the Government of India would like to make an effort to settle the matter. But, taking into consideration the fact that the whole arguments in the case are over, technical and legal issues are involved, I do not think it will be proper for us to do anything now and there are also various bodies like the Public Accounts Committee, other auditing agencies, and Accountant-General to whom the statutory organizations are accountable. Therefore, there is some difficulty in regard to settling this matter at this stage. But, as I have said, it should not affect the procurement as a whole and I am confident that we shall be in a position to have some understanding with the Governments of Punjab and Haryana in the near future.

Mr. SPEAKER Shri Ram Gopal Reddy—not here. Shri R. S. Pandey

श्री राम सहाय पांडे (राजनंदगाव) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो बक्तव्य दिया है, उसमें एक तो यह कहा गया है कि अभी तक फूड कॉर्पोरेशन को 1975-76 के लिए गेहूं के प्रोक्यूरमेंट के लिए आदेश नहीं दिया है, और दूसरे, फूड कॉर्पोरेशन ने पंजाब सरकार को यह सेल्ज टैक्स की रकम देनी है या नहीं, यह मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट के रूप में पेडिंग है। यह एक बड़ा अहम सवाल है। पंजाब से हम बड़ी उम्मीद करते हैं। पंजाब अपने हर कमिटमेंट को पूरा करता है। यह वही प्रदेश है, जिसको इस देश का कैलिफ़ोर्निया, या देश की चीनरी, कहा जाता है। पंजाब ही ऐसा प्रदेश है, जो अन्न संकट के समय देश को खिलाता है। पंजाब ही ऐसा प्रदेश है, जो देश की सोवियेटी

के लिए खतरा उत्पन्न होने पर बन्दूक से लड़ता है।

श्री बरबारा सिंह (होशियारपुर) : लेकिन जब बिग इंडस्ट्री का सवाल आता है, तो पंजाब को कोई इंडस्ट्री नहीं दी जाती है।

श्री राम सहाय पांडे : अगर पंजाब को कोई इंडस्ट्री नहीं दी जाती है, तो हमें माननीय सदस्य से हमदर्दी है। लेकिन पंजाब का औद्योगिकरण न होते हुए भी, वहाँ कोई इंडस्ट्री ने होते हुए भी, उस ने खेती के विकास में बहुत उन्नति की है। पानी, हल, हाइब्रिड सीड, फर्टिलाइजर और ट्रैक्टर आदि का समन्वय कर के वह अनाज पैदा करता है और फूड कार्पोरेशन का देता है।

फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया एक व्हाइट एलिफेंट की तरह है। पंजाब और हरियाणा जो प्रोक्युर करते हैं, उम में से 15 परसेंट खराब हो जाता है—5 परसेंट चोरी हो जाता है, 5 परसेंट चूहे खा जाते हैं और 5 परसेंट सड़-गल जाता है। ये दोनों राज्य जो अनाज पैदा करते हैं और प्रोक्युर करते हैं, उम का 15 परसेंट इस व्हाइट एलिफेंट के अन्तर्गत नष्ट हो जाता है। श्री हरी सिंह ने फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया को फेडरेशन आफ करप्शन आफ इंडिया कहा है। मैं उन की इस बात को एनडॉर्म करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है। जब देश त्राहिमा, त्राहिमा कहता है, तो पंजाब अन्न सप्लाई करता है। मंत्री महोदय बतायें—और अगर उन्हें मालूम न हो, तो वह आफ्रिशल गैलरी से पूछ लें—कि फूड कार्पोरेशन की तरफ पंजाब सरकार का कितना सेल्फ टैक्स बाकी है, और उस ने वह रुपया अभी तक क्यों ही दिया है।

पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब तक जितनी व्हीट आई है, उस में 5,571 टन पंजाब सरकार ने, 3,297 टन पंजाब स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन ने, 3,740 टन पंजाब मार्कफेड ने और बाकी ट्रेडर्स ने खरीदी है। मंत्री महोदय ने कहा है कि अभी तक फूड कार्पोरेशन को प्रोक्युर करने के लिए कोई आदेश नहीं दिया गया है और इस सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित नहीं की है। तो क्या वहाँ कोई प्रोक्युरमेंट नहीं हो रहा है? मंत्री महोदय कहते हैं कि हम ने कोई क्वान्टम निर्धारित नहीं किया है, और यह मेटर सबजूडिस है।

यह सबजूडिस क्या होता है? अगर फूड कार्पोरेशन को कोई रुपया देना है, तो वह फ्रीरन देना चाहिए, और अगर नहीं देना है, तो कहना चाहिए कि नहीं देना है। अगर किसी मामले को काल्ड स्टोरेज में डालना हो, तो कह दिया जाता है कि मामला सबजूडिस है। मंत्री कहना है कि सरकार को फ्रीरन पंजाब सरकार से समझौता करना चाहिए। हम जानते हैं कि जब कोई मामला अदालत में जाता है, तो उस में पांच दस साल लग जाते हैं। मंत्री महोदय बतायें कि क्या पंजाब गवर्नमेंट ने अनआफ्रिशली सरकार को एपरोच किया है कि हम कोर्ट में मामला ले जाने में बिल्कुल इन्ट्रेस्टिड नहीं हैं, कोर्ट से बाहर जो कुछ भी फ़ैसला आप का करना है, वह कर दीजिए। क्या पंजाब सरकार ने इस मामले को कोर्ट से बाहर तय करने की बात कही है या नहीं?

जहाँ तक इस व्हाइट एलिफेंट—फूड कार्पोरेशन—का सवाल है, हम देखते हैं कि जब बाहर से अनाज आता

[श्री राम सहाय पांडे]

है, तो पोर्ट में आग लग जाने से काफ़ी नष्ट हो जाता है, अनाज सड़-गल जाता है, उस को बूहे खा जाते हैं, उस की चोरी होती है। अब यह सेल्ज टैक्स का झगड़ा चल रहा है। आज देश में अन्न की हालत यह है कि हमारा प्रदेश दाने दाने के लिए मोह ताज है। हम पंजाब की प्रशंसा करते हैं कि वह मेहनत से पदा करता है। सरकार जो अनाज प्रोक्युर करती है, उसका एक भाग सड़-गल जाता है। आखिर सरकार पंजाब गवर्नमेंट को सेल्ज टैक्स क्यों नहीं देती है? जो मेहनत कर के अनाज पदा करते हैं, सरकार उन की प्रशंसा करने के बजाये उन के लिए कठिनाइयों पैदा करती है।

यह सबजुडिस वाली बात बिल्कुल ख़राब और अनुचित है। फूड कार्पोरेशन की नीयत ख़राब मालूम होती है और सरकार इस मामले को लटकाना चाहती है। सरकार ने आदेश दिया है, फिर भी वह कहती है कि हम ने आदेश नहीं दिया है। उस ने नीति निर्धारित कर दी है, फिर भी वह कहती है कि नीति निर्धारित नहीं की गई है। यह मामला घोटाले का है। मंत्री महोदय इस को स्पष्ट करे।

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: Mr. Speaker, you come from Punjab, and you know my Ministry's assessment of Punjab's performance. Even in my budget intervention speech I referred to this and I have said how the country is proud of the contribution of the farmers of Punjab, Haryana, etc.—particularly Punjab farmers, they have made very valuable contribution to the economy of the country. So far as sympathy and protecting the interests of the farmers of Punjab are concerned, there are no two opinions on that.

Sir, as far as procurement is concerned, as I said earlier, the Food Corporation is ready to freely operate in the mandi. As far as procurement operations are concerned, procurement would not suffer as a result of this. That impression of the hon. Member should not go round the country that our procurement is likely to be affected. Food Corporation is helpful and their role is complementary in their procurement efforts. The hon. Member asked about the arrears of sales tax according to the State Governments—the sales tax arrears for Punjab are about Rs. 10.54 crores and for Haryana the arrears would be Rs. 9.96 crores. The total arrears of sales tax which is in dispute is Rs. 14.50 crores. But, as I said earlier the Punjab Chief Minister has been good enough to write to my senior colleague that the technicalities should not be taken into consideration and this matter should be settled. Therefore, I made the statement earlier that there is a desire on both sides, that is on the Government of India as well as on the Governments of Punjab and Haryana to settle this matter. The only difficulty is the stage of the judgment. Naturally there are difficulties in settling this matter at this stage. As I have submitted earlier, even assuming for the sake of arguments that the case is likely to go against the Punjab as well as Haryana Governments, the Government of India would explore the possibility of settling them even thereafter. After all, we may have to change the view after consulting the Law Ministry. Our desire is to settle the matter. This case has come up because of the legal position and the technicality of it (Interruptions).

SHRI R. S. PANDEY: Whatever procurement was made by the Food Corporation, the Corporation has realised from all the States. When they have realised it from all the States, they have not done so in the case of Haryana and Punjab Governments.

MR. SPEAKER: I could appreciate your anxiety about Punjab. About Punjab, my request is this. As regards Punjab, there is a difference between the Minister and the gentleman who is standing in the dock. Please do not treat him as a man standing in the dock. He is

standing just like your colleague; he is not in the dock.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: Sir, this matter came up mainly because of the technical position and the legality involved in the case. But, as I have already stated, we are interested in settling the matter even after the court's judgment. The hon. Member mentioned a loss of 5% or so in grains. I express my difficulty in this regard. There may be losses of grains here and there. It may not be more than 2%—mostly it may come to 1½%. In this operation that may be the position anywhere in the world. I may say that there may be some weakness or some failure here and there. But, as far as the general operations of the Food Corporation are concerned, the impression should not go round that there is something wrong with the Corporation. That impression of the hon. Member is not correct. I would request the hon. Member not to make such remarks which are not justified by facts.

12.25 Hrs.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

HUNDRED AND FORTY-FIRST, HUNDRED AND FIFTIETH, HUNDRED AND FIFTY-THIRD AND HUNDRED AND SIXTY-SIXTH REPORTS.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Sir, I beg to present the following Reports of the Public Accounts Committee:—

- (1) Hundred and forty-first Report on action taken by Government on the recommendations contained in their Hundred and Nineteenth Report on Chapter III of the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1971-72, Union Government (Civil), Revenue Receipts Volume II, Direct Taxes relating to Income-tax.
- (2) Hundred and fiftieth Report on action taken by Government on the recommendations contained in their Fifty-first Report on Chapter IV of the Audit Report (Civil), Revenue

Receipts, 1970 and Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1969-70, Central Government (Civil), Revenue Receipts relating to Income-Tax.

- (3) Hundred and fifty-third Report on action taken by Government on the recommendations contained in their Hundred and twenty-eighth Report on Chapter II of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1971 to Union Government (Civil), Revenue Receipts Volume II Direct Taxes relating to Corporation Tax.
- (4) Hundred and sixty-sixth Report on Ban on Trade with Portugal and B.O.A.C. Gold Smuggling Case.

12.27 Hrs.

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

SIXTY-SIXTH REPORT AND MINUTES

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA (Dausa): I beg to present the following Report and Minutes of the Committee on Public Undertakings:

- (i) Sixty-sixth Report of the National Seeds Corporation Limited.
- (ii) Minutes of the sittings of the Committee relating to the above Report.

12.27 Hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

- (i) Political and constitutional issues raised by Shri Mange Ram's resignation from the Executive Council of Delhi Metropolitan Council.

श्री मधु लिमये (बाँका) : अध्यक्ष महोदय, एक अरसे से मैं यह प्रश्न उठाना चाहता था। दिल्ली में एग्जिक्यूटिव कौंसिल के एक सदस्य श्री मंगे राम ने जो इस्तीफा दिया है अगर